



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1226 वर्ष 2026

लाल सिंह @ ललता प्रसाद .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अरविंद अग्रवाल

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री अरविंद अग्रवाल, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त हैं, तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 460 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - टूंडला, जिला - फिरोजाबाद में, विचारण के तबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक और सह-अभियुक्त मोहन तथा लव द्वारा मृतक को पकड़ने तथा सह-अभियुक्त आकाश द्वारा उसे गोली मारने का कथन है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 15.10.2025 को लगभग 07:45 बजे सायं कृषि क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग तीन घंटों की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई थी। तत्पश्चात्, प्रत्यक्षदर्शी ने आवेदक के संबंध में अपना बयान बदलकर उकसाने की भूमिका का उल्लेख किया है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पर दो मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। आवेदक दिनांक 16.10.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक के उकसावे पर मुख्य अभियुक्त आकाश ने उक्त अपराध कारित किया, परंतु यह सत्य है कि अभियुक्त आकाश का प्रकरण अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से भिन्न हो सकता है।
9. उच्चतम न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) SCC 648 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।

10. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" का सुविदित सिद्धांत जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पुनः प्रतिपादित किया गया है।
12. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष रोसादिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में पुनः इस बात पर बत दिया है कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए, को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।
14. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का प्रकरण मुख्य शूटर आकाश से भिन्न आधार पर है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - लाल सिंह @ ललता प्रसाद को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 16 जनवरी, 2026 विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"